ACCOUNTABILITY INITIATIVE | 15 years

संक्षिप्त

राजस्थान बजट 2023-24

धन और व्यय के स्त्रोत

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान सरकार ने कुल प्राप्तियों के लिए ₹3,90,943 करोड़ आवंटित किए हैं। यह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (जिसे बजट एस्टीमेट भी कहते हैं[1]) से 13 प्रतिशत अधिक है, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (जिसे रिवाइज्ड एस्टीमेट भी कहते हैं[2]) से केवल 2 प्रतिशत अधिक है।

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए:
    - कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अपेक्षित हिस्सा 60 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 4 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमानित हिस्सा 40 फीसदी है।
    - अनुमानित कुल व्यय ₹3,90,856 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 2 प्रतिशत और बजट अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक है।
    - अनुमानित राजस्व व्यय ₹2,58,884 करोड़ है, जो कुल व्यय का 66 प्रतिशत है और पिछले साल के संशोधित अनुमान से 4 प्रतिशत अधिक है।
    - पूंजीगत व्यय ₹1,31,973 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 2 प्रतिशत कम है और कुल व्यय का 34 प्रतिशत है।
    - कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र व्यय का अपेक्षित हिस्सा 39 प्रतिशत है।
    - राजकोषीय घाटा ₹62,772 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.98 प्रतिशत है।

- वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में ऋण और अन्य देनदारियां ₹5,16,815 करोड़ थीं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 36.56 प्रतिशत था। यह वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹5,79,781 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 36.78 प्रतिशत है।

---

[1] अनुमानित बजट आगामी वित्त वर्ष में मंत्रालय या योजना के लिए बजट आवंटित धन के संभावित व्यय का पूर्वानुमान होता है।

[2] संशोधित अनुमान संभावित व्यय की मध्य वर्ष समीक्षा होता है। यह बाकी खर्च, नई सेवाओं और सेवाओं के नए साधन आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है।

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

- वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक शिक्षा के लिए ₹19,294 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें समग्र शिक्षा के लिए ₹14,071 करोड़ शामिल है। माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुमानित राशि ₹12,713 करोड़ है, जिसमें समग्र शिक्षा के लिए ₹2,262 करोड़ शामिल है।

समग्र शिक्षा भारत सरकार की प्रमुख स्कूली शिक्षा योजना है। यह योजना आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हमारे विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 30 नवंबर 2022 तक, राजस्थान को वित्त वर्ष में समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिस्से का आधे से थोड़ा अधिक धन जारी हुआ था।

- पीएम पोशन (पूर्व मध्याह्न भोजन योजना) के प्रावधान के लिए ₹2,204 करोड़ आवंटित किये गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार मुफ्त दूध उपलब्ध कराया जाता है, के लिए ₹864 करोड़ शामिल है। अब यह योजना ₹1,000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ हर दिन बच्चों को दूध उपलब्ध कराएगी।

- वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार की ओर से राजस्थान में पीएम पोषण के लिए ₹761 करोड़ का आवंटन अपेक्षित है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 23 प्रतिशत कम है।
- हमारे विश्लेषण के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान के लिए भारत सरकार द्वारा जारी फंड राष्ट्रीय औसत (53 प्रतिशत) से कम था। दिसंबर 2022 तक स्वीकृत बजट का 51 प्रतिशत ही जारी किया गया था।

- सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा आठ से बारह को शामिल करने के साथ अब पहली से बारहवीं तक सभी ग्रेडों तक मुफ्त शिक्षा का विस्तार किया गया है।
- दसवीं कक्षा के 10,000 छात्रों के लिए राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा (आरटीएसई) की घोषणा की गई है।
- सरकारी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म की घोषणा की गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹560 करोड़ है।
- 100 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, 300 विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा और 300 विद्यालयों में नए विषय शुरू किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

- चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, आयुष क्षेत्र सहित, राजस्थान सरकार ने ₹15,616 करोड़ का प्रस्ताव दिया, जिसमें:
    - चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹5,186 करोड़,
    - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ₹2,100 करोड़, और
    - मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के लिए ₹1,179 करोड़ हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, ₹3,623 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए ₹2,842 करोड़ शामिल है।

हमारे विश्लेषण के अनुसार, राजस्थान के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति, रिलीज और व्यय के बीच अंतर थे। वित्त वर्ष 2021-22 में, प्रस्तावित बजट ₹5,411 करोड़ था, जिसमें से ₹4,492 करोड़ (83 प्रतिशत) स्वीकृत किया गया। हालांकि, केवल ₹3,212 करोड़ या 71 प्रतिशत स्वीकृत बजट जारी किया गया। परिणामस्वरूप, राज्यों के पास खर्च करने के लिए ₹4,480 करोड़ उपलब्ध थे (₹1,268 करोड़ की अव्ययित शेष राशि सहित), जिसमें से 72 प्रतिशत या ₹3,230 करोड़ खर्च किए गए थे।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के लिए स्वीकृत बजट में 65 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए, 16 प्रतिशत एनआरएचएम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) फ्लेक्सीपूल के लिए, 5 प्रतिशत गैर संचारी रोग (एनसीडी) फ्लेक्सीपूल के लिए, 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए और 2 प्रतिशत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के लिए थी।

राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्टाफ की कमी है। 31 मार्च 2021 तक चिकित्सक के स्वीकृत पदों में से मात्र 86 प्रतिशत ही भरे गये थे। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से मात्र 37 प्रतिशत पद ही भरे गये थे।

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।

- ₹1,000 करोड़ के बजट के साथ प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर के लिए नए मेडिकल कॉलेज और ₹500 करोड़ के बजट के साथ जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन की घोषणा की गई है:
    - तीन उप-जिला अस्पतालों को जिला अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा,
    - 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को उप-जिला अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा,
    - 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा, और
    - 14 नए पीएचसी और 33 उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए ₹19,891 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें
    - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए ₹4,731 करोड़,
    - स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के लिए ₹1,146 करोड़,
    - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए ₹1,000 करोड़, और
    - पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को राज्य वित्त आयोग के तहत ₹5,000 करोड़ का अनुदान और केंद्रीय वित्त आयोग के तहत ₹2,989 करोड़ का अनुदान है।

- महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी आय योजना शुरू की गई है, जो मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत, 125 दिनों (पहले यह अवधि 100 दिन थी) के रोजगार की गारंटी देती है।

- हमारे विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 4 जनवरी 2023 तक, राजस्थान में भुगतान की जाने वाली औसत न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित दरों से कम थी। ₹231 की अधिसूचित दर के मुकाबले ₹194 की औसत मजदूरी दी गयी।
- वित्त वर्ष 2022-23 में 4 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कुल देय भुगतान का 12 प्रतिशत मजदूरी लागत पर था।
- राजस्थान में वित्त वर्ष 2022-23 में 4 जनवरी 2023 तक मांग के मुकाबले में दिया गया रोजगार केवल 75 प्रतिशत था।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन ₹500-₹750 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दी गई है।
- गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। ₹200 करोड़ का गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड भी प्रस्तावित किया गया है।

आवास और शहरी विकास

- आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए ₹14,743 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है, जिसमें:
    - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत मिशन) 2.0 के लिए ₹3,054 करोड़,
    - स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए ₹1,324 करोड़,
    - इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹650 करोड़, और
    - प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ₹320 करोड़ हैं।

- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य 2.17 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है।
- डे-एनयूएलएम के तहत 3,000 स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे और 'रिवॉल्विंग' फंड मुहैया कराया जाएगा।
- 40,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) बनाए जाएंगे।

महिला व बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रम के लिए ₹988 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसमें:
    - इंदिरा महिला शक्ति योजना (आई एम शक्ति) के लिए ₹582 करोड़ और
    - मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ₹320 करोड़ हैं।

- बाल विकास सेवाओं के लिए ₹3,057 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसमें:
  - आईसीडीएस के लिए ₹1,315 करोड़,
  - पूरक पोषण के लिए ₹1,205 करोड़,
  - पीएम मातृ वंदना योजना के लिए ₹190 करोड़,
  - राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए ₹128 करोड़, और
  - इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए ₹115 करोड़ हैं।

- प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर योजना के तहत 500 दिवसीय देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- साधारण रोडवेज बसों के किराए में 50 प्रतिशत रियायत के साथ महिला विशेष बस सेवा की घोषणा की गई है।
- ₹320 करोड़ के बजट के साथ 800 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 2,000 नए मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की घोषणा की गई।
- ₹180 करोड़ के बजट के साथ 17 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बच्चों को वर्दी के दो सेट प्रदान किए जाएंगे।

यह प्रकाशन अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित 'At A Glance: Rajasthan Budget 2023-24' का हिंदी संस्करण है, जिसे शरद पांडे, अपराजिता वर्मा, पूनम चौधरी, प्रतीक गुप्ता, जान्हवी और अवंतिका श्रीवास्तव ने तयार किया है।